गौमाता राष्ट्रमाता
स्वतःस्फूर्त गौ-प्रतिष्ठा आन्दोलन

हिन्दी दैनिक
राष्ट्रीय स्वाभिमान

RNI No. : MAHHIN/2008/24084.
www.rashtriyaswabhimaan.com

वर्ष : 18 अंक : 39 मुंबई, मंगलवार, 04 अगस्त 2026 पृष्ठ : 4 मूल्य 1 रुपए

तीन राज्यों के उपचुनाव में मिले अलग-अलग राजनीतिक संदेश, बिहार में प्रशांत किशोर का बड़ा धमाका, दतिया में कांग्रेस की वापसी और गुजरात में भाजपा का अजेय किला बरकरार

नई दिल्ली/पटना/भोपाल/वडोदरा। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजों ने राष्ट्रीय राजनीति को नए संकेत दिए हैं। तीनों राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक तस्वीर सामने आई है। बिहार की सबसे चर्चित बांकीपुर सीट पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के मजबूत गढ़ में सेंध लगाते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस ने भाजपा से सीट छीन ली, जबकि गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर सीट पर भाजपा ने अपना अभेद्य किला कायम रखते हुए एक बार फिर बड़ी जीत हासिल की। इन नतीजों ने जहां बिहार की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा तेज कर दी है, वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी ओर गुजरात में भाजपा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि शहरी क्षेत्रों में उसका संगठनात्मक आधार अब भी बेहद मजबूत बना हुआ है।

सबसे अधिक चर्चा बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट की रही, जहां जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनावी सफलता हासिल की। यह सीट लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां से लगातार पांच बार विधायक रहे थे, जबकि इससे पहले उनके पिता भी इस सीट का कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके थे। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी, जिस पर उपचुनाव कराया गया। चुनाव परिणाम ने सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया। प्रशांत किशोर ने 64,151 मत हासिल कर 49 प्रतिशत से अधिक वोट शेयर के साथ जीत दर्ज की, जबकि भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले। दोनों के बीच जीत का अंतर 19,324 मत रहा। राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं।

बांकीपुर का परिणाम केवल एक सीट का चुनावी नतीजा नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बिहार की राजनीति में उभरते नए राजनीतिक विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। सबसे

उल्लेखनीय तथ्य यह रहा कि भाजपा और राजद दोनों के कुल मतों से भी अधिक वोट अकेले प्रशांत किशोर को मिले। भाजपा और राजद को मिलाकर जहां 59,100 मत प्राप्त हुए, वहीं प्रशांत किशोर ने अकेले 64 हजार से अधिक वोट हासिल किए। इस अंतर ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि उन्होंने पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों से अलग व्यापक जनसमर्थन अर्जित किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह समर्थन आगामी विधानसभा चुनावों तक बना रहता है तो बिहार की राजनीति में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना और मजबूत हो सकती है।

यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी राज्यभर में लगभग चार प्रतिशत मत हासिल करने के बावजूद एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी थी। ऐसे में महज कुछ वर्षों के भीतर भाजपा के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले निर्वाचन क्षेत्र में जीत दर्ज करना प्रशांत किशोर के लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है। इस परिणाम ने भाजपा और राजद दोनों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है।

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने कड़ा मुकाबला जीतते हुए भाजपा से सीट छीन ली। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने 66,757 मत प्राप्त कर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 6,016 वोटों से पराजित किया। भाजपा उम्मीदवार को 60,741 मत मिले। इस चुनाव में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के उम्मीदवार दामोदर यादव 'मंडल' ने भी 22,527 वोट प्राप्त कर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। लगभग 14 प्रतिशत वोट हासिल कर उन्होंने चुनावी समीकरणों को प्रभावित किया, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस बढ़त बनाए रखने में सफल रही।

दतिया उपचुनाव का सबसे चर्चित पहलू भाजपा द्वारा पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना रहा। पार्टी ने उनकी जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया था। चुनाव प्रचार के दौरान नरोत्तम मिश्रा लगातार सक्रिय रहे और उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में व्यापक प्रचार भी किया। इसके बावजूद भाजपा सीट बचाने में असफल रही। चुनाव परिणाम के बाद राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या टिकट परिवर्तन का फैसला भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखी, जिसका असर मतदान पर पड़ा। हालांकि भाजपा ने अभी तक हार के कारणों पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।

दतिया की हार को केवल एक उपचुनाव की पराजय नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। डॉ. नरोत्तम मिश्रा लंबे समय तक इस क्षेत्र की राजनीति का प्रमुख चेहरा रहे हैं। ऐसे में इस सीट पर भाजपा की हार उनके राजनीतिक प्रभाव और संगठनात्मक पकड़ को लेकर भी कई सवाल खड़े कर रही है। वहीं कांग्रेस के लिए यह जीत संगठन में नया उत्साह भरने वाली मानी जा रही है।

उधर गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने अपना मजबूत जनाधार एक बार फिर साबित कर दिया। भाजपा उम्मीदवार सतेंद्रभाई (सतीश) पटेल ने कांग्रेस के भीखाभाई रबारी को 30 हजार से अधिक मतों के बड़े अंतर से पराजित किया। भाजपा उम्मीदवार को 55,084 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी 24,585 मत ही प्राप्त कर सके। इस तरह भाजपा ने लगातार इस सीट पर अपना विजय अभियान कायम रखा। यह सीट विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद रिक्त हुई थी।

मांजलपुर में मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम, लगभग 37.5 प्रतिशत रहा था। कम मतदान के कारण विपक्ष को उम्मीद थी कि परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं, लेकिन मतगणना शुरू होने के बाद शुरुआती दौर से ही भाजपा ने निर्णायक बढ़त बना ली। सभी 19 राउंड की मतगणना में भाजपा उम्मीदवार लगातार आगे रहे और अंततः बड़ी जीत दर्ज की। पोस्टल बैलेट में भी भाजपा को कांग्रेस की तुलना में अधिक समर्थन मिला। नोटा के पक्ष में भी दो हजार से अधिक मत दर्ज किए गए।

इन तीनों उपचुनावों के परिणामों ने अलग-अलग राजनीतिक संदेश दिए हैं। बिहार में प्रशांत किशोर की जीत ने यह संकेत दिया है कि राज्य की राजनीति में पारंपरिक दलों के बीच अब तीसरी राजनीतिक शक्ति भी प्रभावी होती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भाजपा से सीट छीनकर अपनी संगठनात्मक क्षमता का प्रदर्शन किया है, जबकि गुजरात में भाजपा ने एक बार फिर यह साबित किया कि शहरी क्षेत्रों में उसका संगठन और जनाधार अभी भी बेहद मजबूत बना हुआ है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उपचुनावों के परिणामों को सामान्य विधानसभा चुनावों का प्रत्यक्ष संकेत नहीं माना जा सकता, लेकिन ये जनता के तत्काल राजनीतिक रुझानों का महत्वपूर्ण संकेत अवश्य देते हैं। बिहार में भाजपा और राजद दोनों के लिए बांकीपुर का परिणाम आत्ममंथन का विषय बन सकता है। वहीं कांग्रेस दतिया की जीत को मध्य प्रदेश में अपनी वापसी के संकेत के रूप में पेश करेगी। दूसरी ओर गुजरात में भाजपा इस जीत को अपने निरंतर जनसमर्थन और मजबूत संगठन का प्रमाण बताएगी।

युवाओं तक पहुंच बढ़ाने की तैयारी में सीजेपी, दो दिवसीय रणनीतिक बैठक से तय होगी आगे की दिशा

मुंबई। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) अपने संगठनात्मक विस्तार और भविष्य की रणनीति को लेकर दो दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने जा रही है। 5 और 6 अगस्त को छत्रपति संभाजीनगर में होने वाली इस बैठक में पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके, राष्ट्रीय प्रवक्ता, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी तथा विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। माना जा रहा है कि यह बैठक संगठन के लिए आगामी महीनों की दिशा तय करने के लिहाज से अहम साबित होगी, जिसमें युवाओं से जुड़ाव, जनसंपर्क अभियान, संगठनात्मक विस्तार और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर पार्टी की भूमिका को लेकर विस्तृत मंथन किया जाएगा।

पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक में देशभर में संगठन को मजबूत बनाने, विभिन्न राज्यों में सक्रिय कार्यकर्ताओं के नेटवर्क का विस्तार करने और युवाओं के बीच संवाद बढ़ाने की रणनीति पर विशेष चर्चा होगी। इसके अलावा शिक्षा, रोजगार, पारदर्शिता, सामाजिक न्याय और युवाओं से जुड़े अन्य विषयों पर भी संगठन की भावी कार्ययोजना तैयार किए जाने की संभावना है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि बदलते सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में युवाओं की आकांक्षाओं को समझना और उन्हें सीधे संवाद का अवसर देना संगठन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

सीजेपी ने स्पष्ट किया है कि उसका उद्देश्य फिलहाल चुनावी राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना नहीं है। पार्टी का कहना है कि वह स्वयं को पारंपरिक राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने के बजाय सामाजिक और जनसरोकार के मुद्दों पर काम करने वाले एक जनआंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना चाहती है। इसी सोच के तहत बैठक के बाद देशव्यापी ₹लिसनिंग टूर₹ शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के तहत संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता विभिन्न राज्यों का दौरा करेंगे तथा विद्यार्थियों, युवाओं, नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से सीधे संवाद करेंगे। पार्टी का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को भाषण देना नहीं, बल्कि उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं, सुझावों और अनुभवों को सुनना है। संगठन का मानना है कि जमीनी स्तर पर लोगों की वास्तविक चुनौतियों को समझे बिना प्रभावी सामाजिक हस्तक्षेप संभव नहीं है। यही कारण है कि ₹लिसनिंग टूर₹ को संगठन के भविष्य के कार्यक्रमों की आधारशिला माना जा रहा है।

कावेरी जल विवाद फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तमिलनाडु ने कर्नाटक पर आदेशों की अनदेखी का लगाया आरोप; निर्धारित पानी दिलाने की मांग

चेन्नई। दक्षिण भारत के सबसे संवेदनशील अंतरराज्यीय नदी विवादों में शामिल कावेरी जल बंटवारे का मामला एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय की चौखट तक पहुंच गया है। तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कर्नाटक सरकार पर कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) और कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार का कहना है कि कर्नाटक ने निर्धारित मात्रा में पानी नहीं छोड़ा, जिसके कारण तमिलनाडु के किसानों, पेयजल व्यवस्था और सिंचाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तमिलनाडु ने अदालत से मांग की है कि कर्नाटक को तत्काल प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करने और तय मात्रा में पानी छोड़ने का आदेश दिया जाए।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का निर्णय लिया। सरकार का कहना है कि कावेरी जल विवाद को लेकर गठित वैधानिक संस्थाओं द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने के बावजूद उनका पालन नहीं किया गया। ऐसे में संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। राज्य सरकार का तर्क है कि जब कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति के आदेश लागू नहीं हो पा रहे हैं, तब न्यायिक हस्तक्षेप ही एकमात्र प्रभावी उपाय बचता है। तमिलनाडु ने अपनी याचिका में कहा है कि कावेरी नदी का जल बंटवारा किसी एक राज्य की इच्छा पर नहीं, बल्कि न्यायिक आदेशों और वैधानिक संस्थाओं के निर्णयों के आधार पर होता है। इसलिए यदि किसी राज्य द्वारा निर्धारित हिस्से का पानी रोका जाता है तो उसका सीधा असर दूसरे राज्य के लाखों किसानों और नागरिकों पर पड़ता है। सरकार का कहना है कि वर्तमान समय में कावेरी डेल्टा क्षेत्र में धान की खेती का महत्वपूर्ण चरण चल रहा है और समय पर पानी नहीं मिलने से कृषि उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। इसके अलावा कई जिलों में पेयजल आपूर्ति भी कावेरी के जल पर निर्भर है।

विवाद की पृष्ठभूमि 28 जुलाई 2026 को आयोजित कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) की 139वीं बैठक से जुड़ी है। इस बैठक में कावेरी बेसिन के जलाशयों में उपलब्ध जल, वर्षा की स्थिति, जलग्रहण क्षेत्रों की परिस्थितियों और मौसम विभाग के पूर्वानुमानों की विस्तृत समीक्षा की गई थी। सभी तकनीकी पहलुओं पर विचार करने के बाद समिति ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया था कि वह कृष्णराज सागर (केआरएस) और काबिनी बांध से पानी छोड़ते हुए 29 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच तमिलनाडु सीमा पर स्थित बिलिगुंड्लु मापन केंद्र तक प्रतिदिन औसतन 3,500 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराए।

सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावे में करोड़ों की कथित गड़बड़ी से सनसनी, 18 करोड़ रुपये की अनियमितता का दावा; 46 कर्मचारी निलंबित, 9 गिरफ्तार

मुंबई। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति सरकार के भीतर चल रहे मतभेद अब सार्वजनिक मंचों तक पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। नवी मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के वन मंत्री गणेश नाईक ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले नगर विकास विभाग की नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए ऐसा बयान दिया, जिसने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। क्लस्टर विकास योजना और यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन्स (यूडीसीपीआर) को लेकर नाराजगी जताते हुए नाईक ने कहा कि यदि कोई उनसे टकराने की कोशिश करेगा तो उसकी ₹जगह सही नहीं रहने देंगे।₹ उनके इस बयान को सीधे तौर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए राजनीतिक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। महायुति सरकार में शामिल भाजपा, शिवसेना (शिंदे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) के बीच पिछले कुछ समय से विभिन्न मुद्दों पर मतभेदों की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन किसी वरिष्ठ मंत्री द्वारा सार्वजनिक मंच से इस तरह का आक्रामक बयान दिए जाने को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह केवल किसी एक विकास परियोजना का विरोध नहीं, बल्कि सरकार के भीतर नीति

निर्माण और क्षेत्रीय नेतृत्व को लेकर बढ़ते असंतोष का संकेत भी हो सकता है।

अपने संबोधन के दौरान गणेश नाईक ने क्लस्टर विकास योजना के वर्तमान स्वरूप पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि योजना को जिस प्रकार लागू किया जा रहा है, उससे नवी मुंबई जैसे सुव्यवस्थित शहरों की मूल योजना प्रभावित हो सकती है। उनका कहना था कि अत्यधिक एफएसआई और बड़े पैमाने पर पुनर्विकास की अनुमति दिए जाने से कई इलाकों में जनसंख्या का घनत्व असामान्य रूप से बढ़ जाएगा, जिससे नागरिक सुविधाओं पर भारी दबाव पड़ेगा।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सेक्टर-9 जैसे क्षेत्रों में यदि मौजूदा प्रस्तावों के अनुसार विकास किया गया तो वहां इतनी भीड़ बढ़ सकती है कि लोगों के लिए फुटपाथ पर चलना भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर विकास विभाग के कुछ निर्णय नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि अन्य हितों को प्राथमिकता देकर लिए जा रहे हैं। उनके अनुसार किसी भी विकास योजना का उद्देश्य केवल ऊंची इमारतें बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि सड़कें, पार्किंग, जलापूर्ति, सीवरेज, हरित क्षेत्र और सार्वजनिक सुविधाओं का संतुलित विकास भी उतना ही आवश्यक है।

गणेश नाईक ने कहा कि विकास के नाम पर यदि शहरों का मूल स्वरूप ही बिगड़ जाए और नागरिकों का जीवन कठिन हो जाए तो ऐसी योजनाओं पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए कि वह नवी मुंबई के हितों से जुड़े मुद्दों पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर खुलकर विरोध करेंगे।

राजनीतिक हलकों में सबसे अधिक चर्चा उनके उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि यदि कोई उनसे उलझने की कोशिश करेगा तो उसकी ₹जगह सही नहीं रहने देंगे।₹ हालांकि उन्होंने अपने भाषण में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कार्यक्रम का संदर्भ, क्लस्टर योजना पर उनकी टिप्पणी और नगर विकास विभाग पर सीधा हमला देखते हुए इसे उपमुख्यमंत्री एवं नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के लिए राजनीतिक संदेश माना जा रहा है।

यह पहला अवसर नहीं है जब गणेश नाईक ने नगर विकास विभाग के कामकाज पर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी उन्होंने सिडको की मूल्यवान जमीनों के आवंटन को लेकर आपत्ति जताई थी। उनका आरोप था कि महत्वपूर्ण भूखंड निजी बिल्डरों को दिए जा रहे हैं, जिससे सार्वजनिक हित प्रभावित हो सकता है। उन्होंने नवी मुंबई महानगरपालिका के वित्तीय प्रबंधन और विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं को लेकर भी कई बार चिंता व्यक्त की थी।

इसके अलावा प्रभाग रचना में किए गए बदलावों और स्थानीय निकायों से जुड़े प्रशासनिक निर्णयों पर भी उन्होंने शिंदे गुट की कार्यप्रणाली की आलोचना की थी। यही वजह है कि राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि दोनों नेताओं के बीच मतभेद केवल क्लस्टर विकास योजना तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कई प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दों पर लंबे समय से असहमति बनी हुई है।

महायुति सरकार के लिए यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियां तेज हो रही हैं। नवी मुंबई जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में भाजपा और शिवसेना (शिंदे) के बीच तालमेल बनाए रखना गठबंधन के लिए अहम माना जाता है। ऐसे समय में सार्वजनिक रूप से सामने आए इस प्रकार के बयान विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का अवसर भी दे सकते हैं।

शहरी विकास विशेषज्ञों का कहना है कि क्लस्टर विकास योजना का उद्देश्य पुराने और जर्जर भवनों का पुनर्विकास कर आधुनिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन ऐसी किसी भी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि स्थानीय आधारभूत ढांचा बढ़ती आबादी का दबाव झेलने के लिए कितना तैयार है। यदि सड़कें, जल निकासी, सार्वजनिक परिवहन, स्कूल, अस्पताल और अन्य नागरिक सुविधाएं समान अनुपात में विकसित नहीं की जातीं तो पुनर्विकास की योजनाएं भविष्य में नई समस्याएं भी पैदा कर सकती हैं।

दूसरी ओर, नगर विकास विभाग का पक्ष यह रहा है कि क्लस्टर विकास योजना शहरी पुनर्विकास को गति देने, पुराने और असुरक्षित भवनों का पुनर्निर्माण करने तथा नागरिकों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार की गई है। विभाग का मानना है कि योजना के तहत विकास नियंत्रित नियमों और निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जाएगा।

हालांकि गणेश नाईक के ताजा बयान के बाद महायुति सरकार के भीतर समन्वय को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं।

संपादकीय

चाणक्य और शामशास्त्री

इतिहास केवल उन लोगों का नहीं होता जो साम्राज्य बनाते हैं, युद्ध जीतते हैं या सिंहासन पर बैठते हैं। इतिहास उन मनीषियों का भी होता है जो समय की धूल में दबे ज्ञान को खोजकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। भारत के महान राजनीतिक चिंतक, अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य का नाम आज पूरी दुनिया सम्मान के साथ लेती है। उनका ग्रंथ 'अर्थशास्त्र' शासन, अर्थव्यवस्था, कूटनीति, सुरक्षा, प्रशासन और राज्य संचालन का ऐसा अद्भुत दस्तावेज माना जाता है, जिसकी तुलना विश्व के श्रेष्ठ राजनीतिक ग्रंथों से की जाती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यदि कर्नाटक के एक संस्कृत विद्वान और लाइब्रेरियन रुद्रपटनम शामशास्त्री का अथक परिश्रम न होता, तो संभव है कि यह अमूल्य ग्रंथ आज भी इतिहास के अंधकार में खोया रहता।

रुद्रपटनम शामशास्त्री का जन्म वर्ष 1865 में कर्नाटक के हासन जिले के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आर्थिक संसाधन सीमित थे, लेकिन ज्ञान के प्रति उनकी लगन असाधारण थी। बचपन से ही उन्होंने संस्कृत भाषा और भारतीय शास्त्रों के अध्ययन में गहरी रुचि दिखाई। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने संस्कृत व्याकरण, साहित्य और प्राचीन भारतीय ग्रंथों का गंभीर अध्ययन किया। उनकी विद्वत्ता ने उन्हें मैसूर के प्रसिद्ध ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया, जहां उन्हें लाइब्रेरियन के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। उस समय इस संस्थान का उद्देश्य देशभर के मंदिरों, मठों, राजघरानों और विद्वानों से प्राप्त प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण और अध्ययन करना था। बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में भारत का बौद्धिक संसार प्राचीन पांडुलिपियों की खोज और उनके संरक्षण में लगा हुआ था। वर्ष 1904 में शामशास्त्री अपने नियमित कार्य के दौरान संस्थान में सुरक्षित ताड़पत्रों की सूची तैयार कर रहे थे। इसी दौरान उनके हाथ एक ऐसा बंडल लगा, जिसने न केवल उनके जीवन की दिशा बदल दी बल्कि भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में अपना स्थान बना लिया। यह बंडल तंजावुर के एक अज्ञात विद्वान ब्राह्मण द्वारा संस्थान को दान किया गया था। वर्षों तक धूल में पड़ा रहने के कारण ताड़पत्र अत्यंत जर्जर हो चुके थे। उन पर लिखी लिपि भी सामान्य देवनागरी या आधुनिक कन्नड़ नहीं थी, बल्कि प्राचीन 'ग्रंथ लिपि' थी, जिसका प्रयोग दक्षिण भारत में संस्कृत ग्रंथों को लिखने के लिए किया जाता था। जब शामशास्त्री ने अत्यंत सावधानी के साथ उन ताड़पत्रों को पढ़ना प्रारंभ किया, तो धीरे-धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी साधारण ग्रंथ के सामने नहीं बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति के साथ उनकी उत्सुकता बढ़ती गई। अंततः उन्होंने पहचान लिया कि यह वही 'अर्थशास्त्र' है, जिसका उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता था, लेकिन जिसकी मूल प्रति सदियों से लापता मानी जाती थी। यह खोज केवल एक पुस्तक मिलने की घटना नहीं थी, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा के एक खोए हुए अध्याय की पुनर्खोज थी। ताड़पत्रों की स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें पढ़ना अत्यंत कठिन कार्य था। कई स्थानों पर पत्ते टूट चुके थे, स्याही धुंधली पड़ चुकी थी और अनेक अक्षर लगभग मिट चुके थे। उस समय आधुनिक तकनीक उपलब्ध नहीं थी। शामशास्त्री घंटों तक दीपक और मोमबत्ती की मंद रोशनी में बैठकर आवर्धक कांच की सहायता से एक-एक अक्षर पढ़ते, उसकी तुलना अन्य पांडुलिपियों से करते और फिर उसका अर्थ निर्धारित करते। यह कार्य महीनों नहीं, बल्कि वर्षों तक चला। उनकी धैर्यपूर्ण साधना ने धीरे-धीरे इस महान ग्रंथ को फिर से जीवित कर दिया। वर्ष 1909 में उन्होंने 'अर्थशास्त्र' का पहला अंग्रेज़ी अनुवाद प्रकाशित किया। इस प्रकाशन ने भारत ही नहीं, पूरे विश्व के विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। पश्चिमी जगत, जो प्राचीन भारत को मुख्यतः आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से जानता था, पहली बार यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि लगभग ढाई हजार वर्ष पहले भारत में शासन, कर व्यवस्था, गुप्तचर तंत्र, विदेश नीति, आर्थिक प्रबंधन, न्याय व्यवस्था, नगर प्रशासन और सैन्य संगठन पर इतना वैज्ञानिक और व्यवस्थित ग्रंथ लिखा जा चुका था। इससे भारत की बौद्धिक परंपरा के प्रति विश्व का दृष्टिकोण भी बदला। चाणक्य का 'अर्थशास्त्र' केवल राजाओं के लिए लिखी गई पुस्तक नहीं है। यह प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक अनुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, संसाधन प्रबंधन, भ्रष्टाचार नियंत्रण, व्यापार, कृषि, न्याय और जनकल्याण जैसे विषयों पर अत्यंत व्यावहारिक विचार प्रस्तुत करता है। आज भी प्रशासन, राजनीति, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के अनेक विद्यार्थी इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं।

आखिर क्यों पूरा नहीं कर पाते शिक्षा मंत्री अपना कार्यकाल

> मोदी सरकार के कार्यकाल के चारों शिक्षा मंत्रियों में से एक भी अपना विज़न लागू करने के लिए स्वतंत्र नहीं था। रणनीतियां ऊपर से बनती थीं। ये ज़रूर है कि हर मंत्री का उसे लागू करने का तरीक़ा अलग हो सकता है जैसे, स्मृति ईरानी ज़्यादा मुखर थीं, जावड़ेकर रणनीतिक चुप्पी वाले व्यक्ति थे।

कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने भारत की शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और सरकार की प्राथमिकताओं पर एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल सिर्फ़ इस्तीफा देने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पर नहीं, बल्कि मोदी सरकार के दौरान शिक्षा मंत्रालय की पूरी दिशा को लेकर भी उठ रहे हैं। साल 2014 से केंद्र में सत्ता में आने के बाद से अब तक मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री रही स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल 'निशंक' और धर्मेंद्र प्रधान को अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। पांचवा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को बनाया गया है, हालांकि जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मोदी सरकार को तय करना है कि जोशी ही पूर्णकालिक शिक्षा मंत्री रहेंगे या किसी नए चेहरे की तलाश करके उसको स्वतंत्र रूप से शिक्षा मंत्री के पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जोशी भी विवादों में रहे हैं। साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो गैंग रेप और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में उम्र क़ैद की सज़ा काट रहे 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई पर जब चौतरफ़ा सवाल उठ रहे थे, तब प्रल्हाद जोशी ने इसका बचाव किया था।

सवाल यही है कि आखिरकार कोई भी शिक्षा मंत्री अपना कार्यकाल क्यों नहीं पूरा कर पाया। मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में शिक्षा मंत्रालय ही ऐसा प्रमुख मंत्रालय रहा, जिसकी कमान पांच अलग-अलग मंत्रियों ने संभाली वहीं, गृह, विदेश, वित्त, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे मंत्रालयों में अपेक्षाकृत स्थिरता बनी रही। शिक्षा, संस्कृति और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (आईएनबी) ऐसे कुछ चुनिंदा मंत्रालय हैं, जिन्हें सॉफ्ट पावर की तरह देखा जाता है और जो संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अहम रहे हैं।

यही कारण है कि यहां विवाद ज़्यादा हुए और अस्थिरता भी उतनी ही दिखती है। गौरतलब है कि आईएनबी में 12 साल के भीतर सात केंद्रीय मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में पांच केंद्रीय मंत्री बने हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय संभाला मोदी के दूसरे कार्यकाल में यह ज़िम्मेदारी रमेश पोखरियाल 'निशंक' को मिली। मगर 2021 में हुए कैबिनेट विस्तार के दौरान धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री बना दिया गया, जिनके इस्तीफ़े की मांग को लेकर एक महीने तक कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक जंतर-मंतर पर बैठे रहे और आख़िरकार केंद्र सरकार दबाव में आई और प्रधान को इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा।

नीट परीक्षा के लीक होने का मामला अलग कर दें, तो संघ से जुड़े उन सभी प्रमुख लक्ष्यों को धर्मेंद्र प्रधान बिना शोर-शराबा किए लागू करा पाने में सफल रहे हैं, जिनकी कोशिश उनके पूर्ववर्तियों ने ज़ोर लगाते हुए की और विवादों में फंसते गए। ग़ौरतलब है कि 2014 में बनी पहली मोदी कैबिनेट में धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया, फिर मोदी के दूसरे कार्यकाल में वे शिक्षा मंत्री बने और मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी यह ज़िम्मेदारी जारी रही। प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को बढ़ावा मिला। मातृभाषा और कई भाषाओं में शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया। मगर तीन-भाषा फ़ॉर्मूला पर तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ लंबे समय तक वे विवाद के केंद्र में भी रहे। विरोधियों ने उन पर राजनीतिक हस्तक्षेप और हिंदी थोपने का आरोप लगाया, जिससे शिक्षा नीति केंद्र बनाम राज्य के विवाद का मुद्दा बन गई।

मोदी सरकार के कार्यकाल के चारों शिक्षा मंत्रियों में से एक भी अपना विज़न लागू करने के लिए स्वतंत्र नहीं था। रणनीतियां ऊपर से बनती थीं। ये ज़रूर है कि हर मंत्री का उसे लागू करने का तरीक़ा अलग हो सकता है जैसे, स्मृति ईरानी ज़्यादा मुखर थीं, जावड़ेकर रणनीतिक चुप्पी वाले व्यक्ति थे। मोदी के शासन में शिक्षा विभाग में जो भी नीतियां अपनाई गईं, वे सभी वाम विचारधारा को हटाने के मक़सद से लागू हुईं। संघ का मक़सद भारत की शिक्षा व्यवस्था से वाम विचारधारा वाली शिक्षा-पद्धति को हटाना है, क्योंकि संघ मानता है कि वे मुग़लों के समर्थक रहे हैं। संघ की नज़र में, मुग़ल घुसपैठिए हैं और देश की मुस्लिम आबादी उनकी वंशज है। संघ पर आरोप लगते रहें कि इस एजेंडे को पूरा मोदी सरकार के जरिए कराया जा रहा है।

इसी लक्ष्य को साधने के लिए मोदी सरकार के चार शिक्षा मंत्रियों के चयन का पैमाना रहा है। स्मृति ईरानी को छोड़ दें, तो नवनियुक्त शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल 'निशंक' और धर्मेंद्र प्रधान संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। वाजपेयी के ज़माने में भी संघ से आने वाले मुरली मनोहर जोशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था, जो दर्शाता है कि संघ इस मंत्रालय में अपना दख़ल हमेशा चाहता रहा है। स्मृति ईरानी के साथ उनके नाम पर डिग्री विवाद, जेएनयू विवाद और रोहित वेमुला की आत्महत्या जैसे विवाद जुड़ चुके थे।

स्मृति ईरानी संघ की पृष्ठभूमि से नहीं थीं। नई शिक्षा नीति तैयार करने और उसे लागू करने में देरी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्मृति से बहुत खुश नहीं था। संघ के संदेशों को समझना आसान नहीं है। संघ शोर-शराबा नहीं करता। यही कारण है कि फिलाहल संघ की पृष्ठभमि वाले प्रकाश जोशी को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। मंत्रालय में स्मृति ईरानी के कार्यकाल के दौरान नई शिक्षा नीति पर काम की शुरुआत हुई। मोदी के कार्यकाल के तीसरे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' के समय इसे लागू किया गया।

शिक्षा मंत्री रहे निशंक की पहचान संघ से आने वाले एक विद्वान की रही है, जो संघ के मक़सद को आगे ले जा सकते थे। हालांकि, अपने अवैज्ञानिक बयानों को लेकर भी वे विवादों में आए। उन्होंने यहां तक कहा कि चरक ऋषि ने अणु-परमाणु की खोज की थी। कोविड के समय जेईई-नीट की परीक्षा कराए जाने की घोषणा के बाद निशंक के ख़िलाफ़ काफ़ी ऑनलाइन विरोध हुआ था। विरोध में लोग कोर्ट भी गए, जहां सरकार के पक्ष में फ़ैसला आया। हालांकि, तब बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देने से रह गए, जिसे लेकर विवाद हुआ। उनके समय भी आरोप लगे कि नई शिक्षा नीति के ज़रिए केंद्र सरकार शिक्षा पर नियंत्रण अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही है, जिसे उन्होंने नकार दिया था।

शिक्षा मंत्रालय के जरिए मोदी सरकार का सारा जोर संघ को साधने में रहा है, किन्तु शिक्षा के उत्थान के लिए बजट को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। इसी कारण शिक्षा मंत्रालय में बजट घटता गया और विवाद बढ़ते गए। केंद्रीय बजट में शिक्षा मंत्रालय की हिस्सेदारी पिछले 12 वर्षों में तेज़ी से घटी है यह हिस्सा 2013-14 में कांग्रेस-नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में 4.6% था, जो 2025-26 में घटकर 2.5% रह गया। शिक्षा का घटता बजट ही दर्शाता है कि मोदी सरकार शिक्षा में सुधार को लेकर गंभीर नहीं है। चारों शिक्षा मंत्रियों के समय में लगभग हर विश्वविद्यालय में बड़े स्तर पर फ़ैकल्टी के चयन में संघ की विचारधारा को प्राथमिकता दी गई है।

सरोकार

बंधन नहीं, आशीर्वाद बने संबंध: प्रेम की वह ज्योति जो आत्मा को मुक्त कर देती है

मनुष्य के जीवन में यदि कोई भावना सबसे अधिक पवित्र, सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे अधिक परिवर्तनकारी मानी गई है, तो वह प्रेम है। प्रेम केवल दो व्यक्तियों के बीच का भाव नहीं, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि को जोड़ने वाली वह अदृश्य शक्ति है, जिसके कारण जीवन में अपनापन, करुणा, विश्वास और आनंद का अनुभव होता है। किंतु यही प्रेम तब अपना वास्तविक स्वरूप खो देता है, जब उसमें स्वार्थ, अधिकार, भय और अपेक्षाओं का प्रवेश हो जाता है। तब वह प्रेम नहीं रह जाता, बल्कि मोह का रूप धारण कर लेता है। दुर्भाग्य से आज अधिकांश लोग इसी मोह को प्रेम समझ बैठते हैं और फिर जब रिश्तों में कड़वाहट आती है, तो प्रेम को दोष देने लगते हैं। जबकि सत्य यह है कि प्रेम कभी पीड़ा का कारण नहीं बनता, पीड़ा का कारण केवल मोह होता है।

मानव जीवन में जितने भी संबंध हैं, वे तभी तक सुंदर बने रहते हैं जब तक उनमें स्वतंत्रता, सम्मान और विश्वास बना रहता है। जैसे ही कोई व्यक्ति दूसरे को अपने अधिकार की वस्तु समझने लगता है, संबंधों की मिठास धीरे-धीरे समाप्त होने लगती है। संसार में अनेक लोग यह मानते हैं कि जिस व्यक्ति पर उनका सबसे अधिक अधिकार है, वही उनसे सबसे अधिक प्रेम करता है। लेकिन यह धारणा हमेशा सही नहीं होती। प्रेम किसी पर अधिकार जताने का नाम नहीं है, बल्कि उसके जीवन को सहज, सुरक्षित और सुखी बनाने की भावना का नाम है। प्रेम किसी को अपने अनुसार ढालने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उसके वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करता है।

भगवान श्रीकृष्ण ने अपने जीवन के प्रत्येक संबंध में यही संदेश दिया कि प्रेम का आधार स्वार्थ नहीं, बल्कि समर्पण होना चाहिए। उन्होंने किसी से प्रेम किया तो उसके कल्याण के लिए किया, न कि उसे अपने बंधन में रखने के लिए। चाहे माता यशोदा का वात्सल्य हो, सुदामा की मित्रता हो, अर्जुन के प्रति उनका स्नेह हो या वृंदावन की गोपियों के प्रति उनका दिव्य प्रेम—हर संबंध में उन्होंने यह सिद्ध किया कि प्रेम आत्मा को ऊँचा उठाता है, जबकि मोह मनुष्य को भीतर से कमजोर बना देता है।

जब मनुष्य किसी से प्रेम करता है, तो उसका पहला विचार सामने वाले की प्रसन्नता होता है। वह यह नहीं सोचता कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह सोचता है कि मैं क्या दे सकता हूँ। यही प्रेम का वास्तविक स्वरूप है। इसके विपरीत मोह हमेशा लेने की इच्छा रखता है। वह चाहता है कि सामने वाला केवल उसकी बात माने, उसी के साथ रहे, उसी के अनुसार चले और उसके बिना किसी अन्य को महत्व न दे। इस प्रकार मोह धीरे-धीरे प्रेम का मुखौटा पहनकर संबंधों में प्रवेश कर जाता है और फिर वही संबंध तनाव, असुरक्षा और दुःख का कारण बनने लगते हैं।

आज के युग में प्रेम का अर्थ भी बहुत सीमित कर दिया गया है। लोग प्रेम को केवल आकर्षण, निकटता या साथ रहने तक ही समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति उनकी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार न करे, तो वे मान लेते हैं कि प्रेम समाप्त हो गया। जबकि सच्चा प्रेम परिस्थितियों के बदलने से समाप्त नहीं होता। वह समय, दूरी और कठिनाइयों से भी अधिक मजबूत बनता है। प्रेम का संबंध शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। आत्मा का संबंध कभी टूटता नहीं, इसलिए प्रेम भी कभी समाप्त नहीं होता।

जीवन में सबसे सुंदर उदाहरण माता-पिता का प्रेम है। एक माता अपने बच्चे के लिए असंख्य कष्ट सहती है। वह उसके लिए अपना आराम, अपनी इच्छाएँ और अपनी सुविधाएँ त्याग देती है। यही निस्वार्थ भाव प्रेम की पहचान है। लेकिन यदि वही माता-पिता अपने बच्चों के प्रत्येक निर्णय पर अधिकार जमाने लगें, उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीने के लिए बाध्य करें और उनकी स्वतंत्र सोच को स्वीकार न करें, तो प्रेम में मोह का प्रवेश हो जाता है। इसलिए प्रेम और अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है।

मित्रता का संबंध भी तभी तक मधुर रहता है, जब तक उसमें स्वार्थ प्रवेश नहीं करता। सच्चा मित्र वह होता है जो बिना किसी लाभ की अपेक्षा के साथ निभाए। वह आपकी सफलता से प्रसन्न हो और आपकी कठिनाइयों में आपके साथ खड़ा रहे। लेकिन यदि मित्रता केवल सुविधा, लाभ या व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण निभाई जाए, तो वह प्रेम नहीं, केवल एक समझौता बनकर रह जाती है।

दांपत्य जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। पति-पत्नी यदि एक-दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं, हर छोटी बात पर अधिकार जताते हैं और हर समय अपनी अपेक्षाओं को सर्वोपरि रखते हैं, तो उनके बीच दूरी बढ़ने लगती है। लेकिन यदि वे एक-दूसरे का सम्मान करें, विश्वास बनाए रखें और एक-दूसरे की स्वतंत्रता का आदर करें, तो उनका संबंध समय के साथ और भी गहरा होता जाता है। प्रेम का अर्थ किसी को अपने लिए बदलना नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर स्वयं बेहतर बनना है।

भारतीय दर्शन में प्रेम को ईश्वर तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग बताया गया है। भक्त और भगवान का संबंध भी प्रेम पर आधारित होता है। भक्त भगवान से कुछ माँगने के लिए नहीं, बल्कि उनके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए जाता है। मीरा, सूरदास, तुलसीदास और चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने प्रेम को भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप माना। उनके लिए प्रेम का अर्थ था—पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास और पूर्ण निष्ठा। यही कारण है कि उनका प्रेम आज भी करोड़ों लोगों के हृदय में प्रेरणा बनकर जीवित है।

यदि मनुष्य अपने जीवन में केवल एक परिवर्तन कर ले कि वह अपने प्रत्येक संबंध से अपेक्षाएँ कम कर दे और देने की भावना बढ़ा दे, तो उसका जीवन पहले से कहीं अधिक सुखी हो सकता है। अधिकांश दुःख इसलिए जन्म लेते हैं क्योंकि हम हर संबंध से कुछ न कुछ पाने की आशा रखते हैं।

जर्सी का रंग बदलने से बदलेगी भारतीय हॉकी की तस्वीर?

भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम की पारंपरिक नीली जर्सी को बदलकर 15 अगस्त से शुरू हो रहे एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 में केसरिया रंग की मुख्य जर्सी पहनाने के निर्णय ने देशभर में नई बहस छेड़ दी है। यह बहस केवल खेल तक सीमित नहीं रही है बल्कि राजनीति, संस्कृति, राष्ट्रीय पहचान और खेल परंपरा तक पहुंच गई है। एक पक्ष इसे खिलाड़ियों की सुविधा और तकनीकी आवश्यकता से जुड़ा निर्णय बता रहा है तो दूसरा पक्ष इसे भारतीय खेलों के कथित 'भगवाकरण' के रूप में देख रहा है। सवाल यह है कि क्या वास्तव में जर्सी का रंग बदलना इतना बड़ा मुद्दा है या यह विवाद मूल प्रश्नों से ध्यान भटका रहा है? सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि हॉकी इंडिया ने जर्सी का रंग बदलने का निर्णय किन आधारों पर लिया। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी रहे दिलीप तिर्की के अनुसार, आज अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मुकाबले नीले सिंथेटिक एस्ट्रो टर्फ पर खेले जाते हैं। ऐसे में नीली जर्सी कई बार मैदान की पृष्ठभूमि में घुल-मिल जाती है, जिससे तेज गति वाले खेल में खिलाड़ियों को अपने साथी खिलाड़ियों की पहचान करने में कठिनाई होती है। आधुनिक हॉकी में खेल की गति अत्यंत तेज हो चुकी है, जहां एक सैकेंड का निर्णय मैच का परिणाम बदल सकता है। पासिंग, पोजिशनिंग और त्वरित निर्णय के लिए खिलाड़ियों की स्पष्ट दृश्यता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसी कारण खिलाड़ियों, कप्तानों, कोचों और सहयोगी स्टाफ से विचार-विमर्श के बाद अधिक स्पष्ट दिखाई देने वाले रंग के रूप में केसरिया को चुना गया। यदि यही वास्तविक कारण है तो इसे केवल तकनीकी दृष्टि से देखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विश्व खेलों में जर्सी के रंग समय-समय पर बदले जाते रहे हैं। फुटबॉल, रग्बी, क्रिकेट, बास्केटबॉल और हॉकी जैसी लगभग सभी खेल प्रतियोगिताओं में टीमें प्रतियोगिता, दृश्यता, प्रायोजकों, प्रसारण गुणवत्ता और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी जर्सियों में परिवर्तन करती रहती हैं। भारतीय हॉकी टीम इससे पहले 2014 विश्व कप में पीली तथा 2018 में हल्के नीले रंग की जर्सी पहन चुकी है। इसलिए रंग परिवर्तन स्वयं में कोई असाधारण घटना नहीं है। विवाद इसलिए बढ़ा है क्योंकि भारतीय हॉकी की पहचान पिछले कई दशकों से नीली जर्सी के साथ जुड़ चुकी है। जैसे ब्राजील की फुटबॉल टीम पीली जर्सी, अर्जेंटीना आसमानी-सफेद धारियों, न्यूजीलैंड 'ऑल ब्लैक्स' और ऑस्ट्रेलिया हरे-पीले रंग से पहचाने जाते हैं, उसी प्रकार भारतीय हॉकी की पहचान भी नीली जर्सी रही है। ओलंपिक स्वर्णिम इतिहास, विश्व कप की उपलब्धियां और अनेक ऐतिहासिक मुकाबलों की स्मृतियां इसी नीली जर्सी से जुड़ी रही हैं। यही कारण है कि पूर्व कप्तान धनराज पिल्लै, परगट सिंह और वीरेन रासकिन्हा जैसे खिलाड़ियों ने चिंता व्यक्त की कि कहीं यह परिवर्तन भारतीय हॉकी की स्थापित पहचान को कमजोर न कर दे।

पूर्व दिग्गज हॉकी खिलाड़ियों की चिंता को भी खारिज नहीं किया जा सकता। खेल केवल तकनीक नहीं, भावनाओं और विरासत का भी विषय होता है। जर्सी केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि करोड़ों प्रशंसकों की स्मृतियों, खिलाड़ियों के गौरव और राष्ट्रीय खेल संस्कृति का प्रतीक होती है। इसलिए ऐसे किसी भी बड़े परिवर्तन से पहले व्यापक संवाद और पारदर्शिता अपेक्षित थी। यदि हॉकी इंडिया खिलाड़ियों और विशेषज्ञों के साथ-साथ पूर्व खिलाड़ियों तथा खेल समुदाय को भी इस निर्णय प्रक्रिया से जोड़ती तो शायद विवाद की तीव्रता कम होती। दूसरी ओर इस पूरे विवाद का राजनीतिक स्वरूप भी कम चिंताजनक नहीं है। विपक्षी दलों ने इसे 'खेलों का भगवाकरण' करार दिया है जबकि कई समर्थकों ने इसे राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक बताया। वस्तुतः दोनों अतिवादी दृष्टिकोण खेल भावना के अनुकूल नहीं हैं। किसी भी रंग का अपना कोई धर्म नहीं होता। रंग प्रतीकों का अर्थ समय, संस्कृति और संदर्भ के अनुसार बदलता रहता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग त्याग, साहस और समर्पण का प्रतीक है। भारतीय सेना, राष्ट्रीय ध्वज, अनेक विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक परंपराओं तथा आध्यात्मिक जीवन में भी केसरिया का सम्मानजनक स्थान है। वहीं इस्लामी परंपराओं, सूफी परंपरा और अनेक एशियाई संस्कृतियों में भी यह रंग विभिन्न रूपों में प्रयुक्त होता रहा है। इसलिए किसी रंग को किसी एक धर्म या विचारधारा का स्थायी प्रतीक मान लेना ऐतिहासिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता।

हालांकि यह भी उतना ही सत्य है कि वर्तमान राजनीतिक वातावरण में रंगों के प्रतीकात्मक अर्थ अत्यधिक संवेदनशील हो चुके हैं। इसलिए जब किसी राष्ट्रीय टीम की दशकों पुरानी पहचान बदली जाती है तो राजनीतिक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठते हैं।

नजरिया

क्या भगवान शिव को हल्दी अर्पित करना उचित है? जानिए परंपरा, आध्यात्मिक संकेत और शास्त्रीय दृष्टिकोण का गूढ़ रहस्य

उत्तराम्नाय ज्योतिष्पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती

सनातन धर्म में प्रत्येक देवी-देवता की आराधना के लिए अलग-अलग पूजन सामग्री निर्धारित की गई है। यह व्यवस्था केवल धार्मिक परंपरा भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक आधार भी छिपा हुआ है। जिस प्रकार भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प प्रिय बताया गया है और भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाने की विशेष परंपरा है, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा में भी कुछ विशिष्ट वस्तुओं का विशेष महत्व बताया गया है। इन्हीं परंपराओं के बीच एक प्रश्न वर्षों से लोगों के मन में उठता रहा है कि क्या शिवलिंग पर हल्दी चढ़ानी चाहिए या नहीं? कई परिवारों में बचपन से यह बात सुनाई जाती है कि भगवान शिव पर हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग इसे धार्मिक नियम मानते हैं, जबकि कुछ इसे केवल लोकमान्यता बताते हैं। ऐसे में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि इस विश्वास का वास्तविक आधार क्या है और धर्म इस विषय में क्या संकेत देता है।

भारतीय संस्कृति में हल्दी केवल एक मसाला नहीं, बल्कि शुभता, समृद्धि और जीवन के मंगल पक्ष का प्रतीक मानी जाती है। विवाह से पहले होने वाली हल्दी की रस्म हो, नववधू का श्रृंगार हो, गृह प्रवेश हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो या फिर किसी नए कार्य का शुभारंभ, लगभग हर मांगलिक अवसर पर हल्दी का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में हल्दी को औषधि का स्थान प्राप्त है तो धर्म में इसे पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि माता पार्वती, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का विशेष महत्व स्वीकार किया गया है। हल्दी का पीला रंग उन्नति, ऊर्जा, जीवन और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसके विपरीत भगवान शिव का स्वरूप संसार के वैभव से परे एक महायोगी का है। उनके शरीर पर भस्म सुशोभित होती है, गले में सर्प विराजमान रहते हैं, जटाओं में गंगा प्रवाहित होती हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र शोभायमान रहता है। वे राजसी वैभव के नहीं, बल्कि वैराग्य और आत्मज्ञान के देवता हैं। शिव का स्वरूप यह संदेश देता है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है और अंततः मनुष्य को सत्य, तप और आत्मबोध की ओर बढ़ना चाहिए। इसी कारण उनकी पूजा में भस्म, बेलपत्र, गंगाजल, धतूरा, आक, शमीपत्र और शुद्ध जल जैसी सामग्री को विशेष महत्व दिया गया है। इन वस्तुओं का संबंध प्रकृति, तपस्या और साधना से माना जाता है।

लोक परंपरा में यह विश्वास विकसित हुआ कि हल्दी का संबंध गृहस्थ जीवन, सौभाग्य और मांगल्य से है, जबकि भगवान शिव तप और संन्यास के प्रतीक हैं। इसी कारण सामान्य शिवलिंग पर हल्दी अर्पित करने की परंपरा नहीं बनी। समय के साथ यह परंपरा इतनी प्रचलित हो गई कि लोगों ने इसे एक कठोर धार्मिक नियम मान लिया। कई स्थानों पर यह भी कहा जाने लगा कि यदि शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाई जाए तो भगवान शिव अप्रसन्न हो जाते हैं। किंतु जब इस विषय को शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाता है तो स्थिति कुछ अलग दिखाई देती है।

प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कोई स्पष्ट विधान उपलब्ध नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि भगवान शिव हल्दी चढ़ाने से क्रोधित हो जाते हैं या इससे कोई बड़ा धार्मिक दोष उत्पन्न होता है। शिवपुराण, लिंगपुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भगवान शिव को प्रिय वस्तुओं का विस्तार से उल्लेख अवश्य मिलता है, लेकिन हल्दी अर्पित करने पर कठोर निषेध का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। इससे यह समझा जा सकता है कि यह मान्यता मुख्य रूप से परंपरागत पूजा-पद्धति और लोकविश्वास पर आधारित है, न कि किसी सार्वभौमिक शास्त्रीय आदेश पर।

धार्मिक परंपराओं में प्रतीकों का अत्यंत महत्व होता है। उदाहरण के लिए भस्म यह स्मरण कराती है कि शरीर नश्वर है और अंततः पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। बेलपत्र मनुष्य के भीतर संतुलन, शुद्धता और शिवतत्त्व के प्रति समर्पण का प्रतीक माना गया है। गंगाजल आत्मशुद्धि का संकेत देता है। धतूरा और आक जैसे पौधे यह संदेश देते हैं कि भगवान शिव उन वस्तुओं को भी स्वीकार कर लेते हैं जिन्हें संसार महत्व नहीं देता। इसी प्रकार हल्दी का प्रतीकात्मक संबंध मांगल्य और गृहस्थ जीवन से जोड़ा गया है।

मालिक जयेश जगशी गाला हेतु प्रकाशक, मुद्रक **अश्विनी कुमार दुबे** द्वारा मोदी प्रिंटर्स, 24 बोमनजी लेन, फोर्ट, मुंबई-400001 (महाराष्ट्र) से मुद्रित कर महाराष्ट्र ग्रेन स्टोर्स, 28, डॉ. भगवानदास इंद्रजीत रोड, वालकेश्वर, मलबार हिल, मुंबई-400006 से प्रकाशित किया।
संपादकः **अश्विनी कुमार दुबे** (पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी है, न्याय क्षेत्र मुंबई), सहसंपादकः सुजीत मिश्रा (दै.'राष्ट्रीय स्वाभिमान 'में सभी लोग सहयोगात्मक और अवैतनिक तौर पर कार्यरत हैं)
● आर.एन.आई.:MAHHIN/2008/24084 ● ईमेलः rastriyaswabhiman@gmail.com ● भ्रमणध्वनि क्र. +919224733113

मुंबई में पैदल यात्रियों को मिलेगा खुला रास्ता, 320 किलोमीटर फुटपाथ होंगे अतिक्रमण मुक्त; बीएमसी आयुक्त ने अधिकारियों को दी कड़ी चेतावनी

मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पैदल चलने वाले लाखों नागरिकों को सुरक्षित, सुगम और बाधारहित आवागमन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने शहरव्यापी स्तर पर एक बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला किया है। 'पेडेस्ट्रियन फर्स्ट' अभियान के तहत पहले चरण में शहर के 320 किलोमीटर लंबे फुटपाथों को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त बनाया जाएगा। बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे ने सभी प्रशासनिक वार्डों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फुटपाथों पर अवैध रूप से कब्जा जमाकर बैठे फेरीवालों, अनधिकृत निर्माण, निर्माण सामग्री, मलबा, लावारिस वाहनों तथा पैदल यात्रियों के आवागमन में बाधा बनने वाली हर वस्तु को तत्काल हटाया जाए। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि इस अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही, ढिलाई या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बीएमसी मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में आयुक्त अश्विनी भिडे ने कहा कि मुंबई जैसे महानगर में प्रतिदिन होने वाली लगभग आधी यात्राएं पैदल पूरी की जाती हैं। ऐसे में फुटपाथ केवल सड़क का हिस्सा नहीं, बल्कि शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यदि फुटपाथ अतिक्रमण, अव्यवस्था और बाधाओं से घिरे रहेंगे तो नागरिकों को मजबूरन सड़क पर चलना पड़ेगा, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ेगा और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि शहर के विकास के साथ-साथ पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

आयुक्त ने सभी सहायक आयुक्तों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने वार्डों में प्रतिदिन फुटपाथों का निरीक्षण करें और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें। प्रत्येक दिन की कार्रवाई का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिसमें कार्रवाई से पहले और बाद की तस्वीरें अनिवार्य रूप से शामिल होंगी। इन रिपोर्टों के आधार पर अभियान की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। उप आयुक्तों को प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करने तथा अतिरिक्त आयुक्तों को प्रत्येक 15 दिन में अभियान की स्थिति का आकलन करने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश न रहे।

बीएमसी ने इस अभियान के लिए उन स्थानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पैदल आवाजाही करते हैं। इनमें स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों, बस स्टॉप, प्रमुख बाजारों, व्यावसायिक क्षेत्रों तथा अत्यधिक भीड़भाड़ वाले मार्गों के फुटपाथ शामिल हैं। इन स्थानों पर पैदल चलने वालों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फुटपाथों पर फैले अवैध कब्जों, निर्माण सामग्री, मलबे, कचरे के ढेर और लावारिस वाहनों को हटाकर उन्हें नागरिकों के उपयोग के लिए पूरी तरह खुला बनाया जाएगा।

अभियान केवल अवैध फेरीवालों तक सीमित नहीं रहेगा। बीएमसी ने उन सभी अवरोधों को हटाने का निर्णय लिया है जो फुटपाथों की उपयोगिता को प्रभावित करते हैं। इसके तहत नियमों के विरुद्ध लगाए गए विज्ञापन बोर्ड, अवैध होर्डिंग, फुटपाथों पर बनाए गए अनधिकृत रैंप, बाहर की ओर खुलने वाले भवनों के दरवाजे तथा अन्य संरचनाएं भी हटाई जाएंगी। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक मार्गों पर किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसा निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे पैदल यात्रियों को असुविधा हो।

आयुक्त अश्विनी भिडे ने स्पष्ट किया कि लाइसेंसधारी फेरीवालों के अधिकारों का भी सम्मान किया जाएगा, लेकिन उन्हें केवल उन्हीं स्थानों पर व्यापार करने की अनुमति होगी जो नियमानुसार निर्धारित किए गए हैं। यदि कोई लाइसेंसधारी विक्रेता भी निर्धारित क्षेत्र से बाहर व्यापार करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं अवैध रूप से फुटपाथों पर कब्जा जमाने वाले फेरीवालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर उन्हें हटाया जाएगा।

बीएमसी ने भविष्य में बनने वाले फुटपाथों की गुणवत्ता को लेकर भी नई नीति अपनाने का निर्णय लिया है। आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि नए फुटपाथ केवल निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप एम-40 ग्रेड कंक्रीट से बनाए जाएं। पेवर ब्लॉक और स्टैम्प कंक्रीट जैसी सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनके कारण रखरखाव की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही पुराने फुटपाथों पर मौजूद गड्ढों, ऊंचाई के असमान स्तर, टूट-फूट और अन्य संरचनात्मक कमियों को भी दूर किया जाएगा, ताकि नागरिकों को सुरक्षित और सुविधाजनक मार्ग उपलब्ध हो सके।

प्रशासन का मानना है कि इस अभियान का सबसे बड़ा लाभ विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं और रोजाना पैदल यात्रा करने वाले लाखों लोगों को मिलेगा। फुटपाथों के व्यवस्थित होने से लोगों को सड़क पर चलने की आवश्यकता कम होगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की संभावना है।

समाजसेविका सुप्रिया चौधरी ने थामा शिवसेना (शिंदे) का दामन, मिली उपशहर संघटिका की जिम्मेदारी

महिला अधिकारों की लड़ाई अब शिवसेना के बैनर तले लड़ने का संकल्प, सैकड़ों महिलाओं ने भी पार्टी में किया प्रवेश

भिवंडी। भिवंडी की चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता एवं पूर्व अपक्ष उम्मीदवार सुप्रिया चौधरी (भोसले) ने शिवसेना (शिंदे) में प्रवेश कर अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की है। पार्टी की ओर से उन्हें भिवंडी पूर्व विधानसभा की उपशहर संघटिका की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौरतलब है कि भिवंडी मनपा चुनाव में कामतघर परिसर के वार्ड क्रमांक 22 से सुप्रिया चौधरी ने अपक्ष उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरकर अपनी अलग पहचान बनाई थी। अब शिवसेना (शिंदे) के उपनेता एवं पूर्व विधायक रुपेश म्हात्रे तथा पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में उन्होंने आधिकारिक रूप से पार्टी में प्रवेश किया। इस अवसर पर उनके साथ सैकड़ों महिलाओं ने भी शिवसेना में शामिल होकर पार्टी को समर्थन दिया।

पार्टी में प्रवेश के बाद सुप्रिया चौधरी ने कहा कि वह शिवसेना की विचारधारा के साथ जुड़कर संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ महिलाओं के हक और अधिकारों के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की समस्याओं और उनके अधिकारों की लड़ाई अब शिवसेना के बैनर तले और मजबूती से लड़ी जाएगी।

इस अवसर पर भिवंडी पूर्व के शहर प्रमुख संजय काबुकर, सचिव समीर पवार, प्रकाश चौधरी, राज पवार, अमोल भोसले, सचिन वेलेकर, सुजाता पामू सहित बड़ी संख्या में शिवसैनिक एवं महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बीयर के पैसे को लेकर विवाद, युवक के सिर पर बोतल से हमला; तीन पर केस

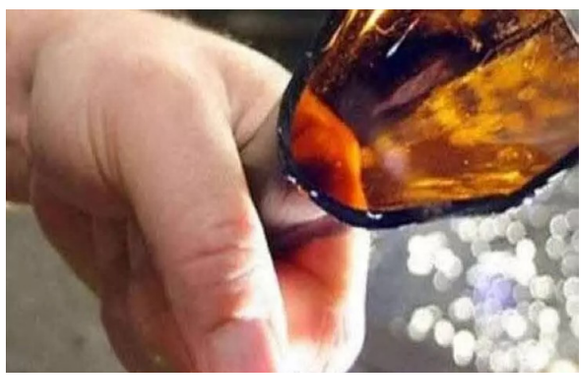

भिवंडी। भिवंडी तालुका के पिंपळास इलाके में बीयर के पैसे को लेकर हुए विवाद में एक युवक के साथ मारपीट कर उसके सिर पर बीयर की बोतल से हमला करने का मामला सामने आया है। कोनगांव पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, 31 जुलाई की रात पिंपळास गांव स्थित रिक्शा स्टैंड पर बीयर की बोतल के पैसे को लेकर विनय म्हात्रे और भावेश रविंद्र म्हात्रे (28) के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि इसी दौरान विनय म्हात्रे, विक्की म्हात्रे और बुगल्या उर्फ विवेक म्हात्रे ने भावेश के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। इनमें से एक आरोपी ने बीयर की बोतल से भावेश के सिर पर वार कर उसे घायल कर दिया।

भावेश की शिकायत पर कोनगांव पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 118(1), 115(2), 352 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं। मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक रोहन गायकवाड कर रहे हैं।

भिवंडी में दो हुक्का पार्लरों पर पुलिस की कार्रवाई, 33 लोगों पर मामला दर्ज

84 हजार 918 रुपये से अधिक का तंबाकूजन्य सामान जब्त, पद्मानगर और नागांव रोड में छापेमारी

भिवंडी। शहर में अवैध रूप से संचालित हुक्का पार्लरों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की। भिवंडी शहर पुलिस और अपराध शाखा की टीम ने तंबाकू मिश्रित हुक्का परोसने और सेवन करने के आरोप में कुल 33 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 84 हजार 918 रुपये कीमत के सिगरेट, तंबाकूजन्य पदार्थ और हुक्का सामग्री जब्त की।

पहली कार्रवाई 1 अगस्त 2026 की शाम करीब 7:30 बजे पद्मानगर के भद्रावतीनगर स्थित साई मंदिर के पास की गई। अपराध शाखा घटक-2 की टीम ने रितेश जाधव के घर में कथित तौर पर चल रहे हुक्का पार्लर पर छापा मारा। पुलिस के अनुसार, स्नेहा उर्फ वहिनी रितेश जाधव और रितेश जाधव के यहां दीपक राममिलन गुप्ता, याकूब मोहम्मद सुलतान अंसारी और गणेश रामरतन भारती के माध्यम से ग्राहकों को तंबाकू मिश्रित फ्लेवर हुक्का उपलब्ध कराया जा रहा था। मौके पर कई युवक हुक्का सेवन करते मिले। पुलिस ने यहां से करीब 70 हजार 200 रुपये कीमत के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद जब्त किए। इस मामले में अपराध शाखा के पुलिस हवलदार भावेश शांताराम घरत की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है।

वहीं, शांतीनगर पुलिस ने नागांव रोड इलाके में चल रहे एक अन्य हुक्का पार्लर पर कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, गैबीनगर निवासी संचालक जाफरअली उर्फ शेरू युसूफ शेख (30) ने अपने मैनेजर और कैशियर के साथ मिलकर ग्राहकों को हुक्का सेवन के लिए जगह उपलब्ध कराई थी। आरोप है कि यहां प्रतिबंधित तंबाकू और निकोटीन युक्त फ्लेवर पदार्थों से तैयार हुक्का परोसा जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 14 हजार 718 रुपये कीमत के सिगरेट और अन्य तंबाकूजन्य पदार्थ जब्त किए।

दोनों मामलों में पुलिस ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (संशोधित) अधिनियम, 2018 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध हुक्का पार्लरों और तंबाकूजन्य पदार्थों की बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

21 साल से फरार चल रहा अभियुक्त गिरफ्तार

मुंबई। पुलिस ने लगभग 21 वर्षों से फरार चल रहे नासिक के व्यवसायी अवधूत चाफेकर (65) को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चाफेकर पर वर्ष 2005 में करीब नौ लाख रुपये की ठगी का आरोप था, जिसके बाद अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। तब से वह फरार चल रहा था।

पुलिस के अनुसार, चाफेकर पिछले दो दशकों से अधिक समय से अपनी पहचान छिपाकर नासिक में रह रहा था। उसने कभी अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन नहीं लिया और पहचान छिपाने के लिए अन्य लोगों के पहचान पत्रों का उपयोग करता रहा। इस दौरान उसने नासिक में एक इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय भी शुरू कर लिया था।

'ललकारा' की स्टारकास्ट में बड़ा बदलाव, फरहान अख्तर ने अभिनय से किया किनारा, अब नई एंट्री की चर्चा तेज

अभिनेता आमिर खान और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर की बहुप्रतीक्षित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'ललकारा' अपनी घोषणा के बाद से ही लगातार चर्चा में बनी हुई है। भारतीय क्रिकेट के इतिहास के महान खिलाड़ी लाला अमरनाथ के जीवन से प्रेरित इस फिल्म को लेकर दर्शकों और फिल्म जगत में खासा उत्साह है। इसी बीच फिल्म से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है, जिसने इसकी स्टारकास्ट को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभिनेता, निर्माता और निर्देशक फरहान अख्तर ने फिल्म में अभिनेता के रूप में काम करने से खुद को अलग कर लिया है। हालांकि वह इस महत्वाकांक्षी परियोजना से पूरी तरह बाहर नहीं हुए हैं और अपनी प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट के माध्यम से निर्माता के रूप में पहले की तरह जुड़े रहेंगे। बताया जा रहा है कि फरहान अख्तर के इस फैसले के पीछे किसी प्रकार का रचनात्मक मतभेद नहीं, बल्कि उनकी व्यस्त पेशेवर प्रतिबद्धताएं हैं। इन दिनों वह निर्देशक नीरज पांडे की आगामी फिल्म की तैयारियों में पूरी तरह व्यस्त हैं, जिसमें उन्हें भारतीय फिल्म संगीत के महान संगीतकार आर.डी. बर्मन की भूमिका निभानी है। इस किरदार के लिए फरहान विशेष तैयारी कर रहे हैं और इसी फिल्म की शूटिंग का कार्यक्रम 'ललकारा' के शूटिंग शेड्यूल से टकरा गया। लगातार बदलते शूटिंग कार्यक्रम और दोनों फिल्मों की समय-सीमा को देखते हुए उन्होंने अभिनेता के रूप में 'ललकारा' से अलग होने का निर्णय लिया। सूत्रों के अनुसार 'ललकारा' में फरहान अख्तर के हिस्से एक बेहद महत्वपूर्ण किरदार था, जो कहानी के भावनात्मक और नाटकीय पक्ष को मजबूत बनाने वाला माना जा रहा था। यही वजह है कि उनके बाहर होने की खबर के बाद फिल्म की नई कास्टिंग को लेकर फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। हालांकि निर्माताओं ने इस बदलाव पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक फरहान अख्तर की जगह अब अभिनेता सिद्धांत गुप्ता का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सिद्धांत फिल्म में आमिर खान के बेहद करीबी मित्र की भूमिका निभा सकते हैं। यदि यह कास्टिंग अंतिम रूप लेती है तो यह सिद्धांत गुप्ता के करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होगी। पिछले कुछ वर्षों में सिद्धांत ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपने दमदार अभिनय से अलग पहचान बनाई है। 'जुबली', 'ब्लैक वारंट' और 'फ्रीडम एट मिडनाइट' जैसी चर्चित वेब सीरीज में उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने सराहा था। अब यदि उन्हें 'ललकारा' जैसी बड़े बजट और चर्चित फिल्म का हिस्सा बनने का अवसर मिलता है तो यह उनके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है।

'ललकारा' को लेकर सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि यह फिल्म करीब ढाई दशक बाद आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर की जोड़ी को फिर से एक साथ ला रही है। वर्ष 2001 में रिलीज हुई 'लगान' ने भारतीय सिनेमा में इतिहास रचा था। फिल्म ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त सफलता हासिल की थी और ऑस्कर पुरस्कारों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। क्रिकेट की पृष्ठभूमि पर बनी उस फिल्म ने खेल, संघर्ष और आत्मसम्मान की कहानी को जिस प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया था, उसने दर्शकों के दिलों में स्थायी जगह बना ली। अब 'ललकारा' को लेकर भी उसी तरह की उम्मीदें व्यक्त की जा रही हैं।

इस बार कहानी भारतीय क्रिकेट के पहले टेस्ट कप्तान रहे लाला अमरनाथ के जीवन और उनके संघर्षों के इर्द-गिर्द बुनी जा रही है। लाला अमरनाथ भारतीय क्रिकेट इतिहास की उन महान हस्तियों में शामिल हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। उनके जीवन में संघर्ष, साहस, नेतृत्व और खेल भावना के अनेक प्रेरक प्रसंग रहे हैं। माना जा रहा है कि फिल्म केवल खेल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उस दौर के सामाजिक और ऐतिहासिक परिवेश को भी बड़े पर्दे पर जीवंत करेगी।

फिल्म का निर्माण एक्सेल एंटरटेनमेंट और राजकुमार हिरानी फिल्म्स मिलकर कर रहे हैं। दोनों प्रोडक्शन हाउस अपनी मजबूत कहानी, उच्च निर्माण गुणवत्ता और दर्शकों से जुड़ने वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं।

16 किलो वजन घटाकर नए अवतार में लौटे सलमान खान, फिटनेस को लेकर किया बड़ा खुलासा, नई फिल्म की तैयारियों ने बढ़ाई उत्सुकता

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर अपने शानदार फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर सुर्खियों में हैं। पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर उनकी नई तस्वीरें और जिम वर्कआउट के वीडियो लगातार चर्चा का विषय बने हुए थे। बदले हुए लुक और पहले से कहीं अधिक फिट नजर आ रहे सलमान को देखकर प्रशंसकों के बीच कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। माना जा रहा था कि अभिनेता अपनी आगामी बड़े बजट की फिल्म 'एसवीसी 63' के लिए खुद को पूरी तरह नए अंदाज में तैयार कर रहे हैं। अब इन सभी चर्चाओं पर खुद सलमान खान ने विराम लगा दिया है। उन्होंने पहली बार खुलासा किया है कि उन्होंने अपने शरीर से पूरे 16 किलो वजन कम किया है, जिसके बाद उनका यह फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन आधिकारिक रूप से चर्चा का केंद्र बन गया है।

सलमान खान ने यह खुलासा अपने भाई सोहेल खान के रियलिटी शो 'अलायंस' में शिरकत करने के दौरान किया। वह शो में प्रतियोगी के रूप में नहीं, बल्कि अपने छोटे भाई का उत्साह बढ़ाने और उनका समर्थन करने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान दोनों भाइयों के बीच हुई हल्की-फुल्की बातचीत ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। माहौल पूरी तरह पारिवारिक और मजाकिया था। इसी दौरान सलमान ने मुस्कुराते हुए सोहेल से उनके फिटनेस सफर के बारे में पूछा और मजाक में कहा कि उनका वजन काफी कम हो गया है। इस पर सोहेल ने गर्व के साथ बताया कि उन्होंने 12 किलो वजन घटाया है। इसके जवाब में सलमान ने सहज अंदाज में कहा, ₹मैंने 16 किलो वजन घटाया है₹ अभिनेता के इस एक वाक्य ने पिछले कई महीनों से चल रही तमाम अटकलों को समाप्त कर दिया।

दरअसल, हाल के दिनों में सलमान खान लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जिम में पसीना बहाते हुए तस्वीरें और वीडियो साझा कर रहे थे। कभी वह वेट ट्रेनिंग करते नजर आए, तो कभी इंटेंस कार्डियो और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते दिखाई दिए। उनकी तस्वीरों में चेहरे की फिटनेस, शरीर की बनावट और ऊर्जा में आए बदलाव को प्रशंसकों ने तुरंत नोटिस किया था। सोशल मीडिया पर उनके नए लुक को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थीं और कई लोगों का मानना था कि अभिनेता अपनी अगली फिल्म के लिए जबरदस्त शारीरिक तैयारी कर रहे हैं। अब उनके बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह बदलाव किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि लंबे समय तक की गई कड़ी मेहनत और अनुशासित जीवनशैली का नतीजा है। सलमान खान का फिटनेस के प्रति समर्पण किसी से छिपा नहीं है।

विदेशी नौकरी के सपनों के पीछे छिपे साइबर गुलामी के काले सच को उजागर करेगी नई वेब सीरीज

डिजिटल दौर में ऑनलाइन ठगी और मानव तस्करी जैसे संगठित अपराध तेजी से नए रूप धारण कर रहे हैं। विदेश में आकर्षक नौकरी, ऊंचे वेतन और सुनहरे भविष्य का सपना दिखाकर युवाओं को जाल में फंसाने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह अब केवल आर्थिक अपराध तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि यह एक ऐसे संगठित नेटवर्क में बदल चुके हैं, जहां इंसानों का इस्तेमाल साइबर अपराध के औजार के रूप में किया जाता है। इसी भयावह और कम चर्चित विषय को केंद्र में रखते हुए प्राइम वीडियो अपनी नई हिंदी ओरिजिनल सीरीज 'जॉब ट्रैफिकिंग' लेकर आ रहा है। प्लेटफॉर्म ने इस बहुप्रतीक्षित सर्वाइवल ड्रामा की पहली झलक जारी कर दी है, जिसने रिलीज से पहले ही दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। आठ एपिसोड में तैयार की गई यह सीरीज केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन हजारों युवाओं की त्रासदी को सामने लाने का प्रयास करती है, जो बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश जाने का सपना देखते हैं और मानव तस्करी तथा साइबर अपराध के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का शिकार बन जाते हैं। निर्देशक प्रशांत नायर ने इस कहानी को ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया है कि दर्शक केवल घटनाओं को देखेंगे ही नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों और मानसिक संघर्षों को भी महसूस करेंगे, जिनसे पीड़ित गुजरते हैं। 'जॉब ट्रैफिकिंग' का निर्माण सेलेक्ट मीडिया होल्डिंग्स और चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को प्रतीक खन्नूजा, समीर चंद, विकेश भूटानी और शुजात सौदागर ने प्रोड्यूस किया है। सीरीज में निमरत कौर, रोशन मैथ्यू, काव्या त्रेहान और पवन मल्होत्रा जैसे सशक्त कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में

दिखाई देंगे। इन कलाकारों के दमदार अभिनय से कहानी में भावनात्मक गहराई और वास्तविकता का अनुभव मिलने की उम्मीद है। सीरीज की कहानी भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न इलाकों की पृष्ठभूमि में आगे बढ़ती है। इसमें उस अपराध जगत की परतें खोली गई हैं, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'पिग बुचेरिंग' स्कैम के नाम से जाना जाता है। यह ऐसा साइबर अपराध है, जिसमें अपराधी पहले लोगों का विश्वास जीतते हैं, फिर उन्हें निवेश, नौकरी या अन्य आकर्षक अवसरों का लालच देकर आर्थिक रूप से पूरी तरह ठग लेते हैं। लेकिन इस सीरीज का सबसे भयावह पक्ष यह है कि इसमें केवल ठगी के शिकार लोगों की कहानी नहीं दिखाई गई है, बल्कि उन युवाओं की दर्दनाक हकीकत भी सामने लाई गई है, जिन्हें नौकरी का झांसा देकर विदेश ले जाया जाता है और बाद में उनकी इच्छा के विरुद्ध साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोहों में काम करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। कहानी का केंद्र तीन ऐसे किरदार हैं, जिनकी दुनिया अलग-अलग है, लेकिन किस्मत उन्हें एक ही अपराध की कड़ी से जोड़ देती है। पहला किरदार एक ऐसा स्कैमर है, जो खुद इस खतरनाक नेटवर्क में फंस चुका है और अब उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। दूसरा किरदार एक ऐसी गृहिणी का है, जो ऑनलाइन ठगी का शिकार बनती है और अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुनती है। तीसरा किरदार एक कॉर्पोरेट सीईओ का है, जिसकी जिंदगी अचानक ऐसी परिस्थितियों में उलझ जाती है, जहां सही और गलत की सीमाएं धुंधली होने लगती हैं। इन तीनों पात्रों की समानांतर यात्रा यह दिखाती है कि साइबर अपराध केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह इंसानी रिश्तों, विश्वास और जीवन को भी गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। सीरीज का कथानक केवल अपराध की घटनाओं को दिखाने तक सीमित नहीं है।

हिन्दी दैनिक
राष्ट्रीय स्वाभिमान

राष्ट्रीय स्वाभिमान
पत्र व्यवहार:रफ्तार इंडिया एक्सप्रेस, 31/33 पहला महला, पत्रावाला बिल्डिंग, वजु कोटक मार्ग लिंक शहीद भगतसिंह रोड, फोर्ट, मुंबई 400001, भ्र.ध्व. क्र.:9224733113
ईमेल:rastriyaswabhimaan@gmail com

04 मुंबई, मंगलवार, 04 अगस्त 2026 महाराष्ट्र
epaper.rashtriyaswabhimaan.in
www.rashtriyaswabhimaan.com

कैप्टन अमोल महाडिक ने समर्थकों के साथ कांग्रेस में किया प्रवेश

आरक्षण के मुद्दे पर जातियों में विवाद पैदा कर रही सरकार:हर्षवर्धन सपकाल

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे के भांजे कैप्टन अमोल महाडिक ने अपने समर्थकों के साथ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की मौजूदगी में तिलक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। प्रदेशाध्यक्ष सपकाल ने उनका कांग्रेस परिवार में स्वागत करते हुए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के सचिव एवं तेलंगाना के सहप्रभारी सचिन सावंत, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अतुल लोंढे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दरकिनार कर भाजपा सरकार का मनमाना शासन चल रहा है, जो देश के लिए बेहद खतरनाक है। इसी के खिलाफ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ा संघर्ष शुरू किया है। देश को तानाशाही प्रवृत्तियों से बचाना सबसे महत्वपूर्ण है और राहुल गांधी के इस संघर्ष को देशभर से समर्थन मिल रहा है। युवाओं में

भी उनके प्रति बड़ा समर्थन देखने को मिल रहा है।

सपकाल ने कहा कि राहुल गांधी के संघर्ष को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कैप्टन अमोल महाडिक ने भी इसी विचार के साथ कांग्रेस में प्रवेश किया है। उन्होंने कहा कि देश को सही मायने में कांग्रेस की विचारधारा और राहुल गांधी का नेतृत्व ही आगे ले जा सकता है। अमोल महाडिक को प्रोफेशनल कांग्रेस विभाग में काम करने का अवसर दिया जाएगा और उनके अनुभव का पार्टी को लाभ मिलेगा।

कांग्रेस में प्रवेश के बाद अमोल महाडिक ने कहा कि उनका परिवार कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा रहा है। उनके दादा दत्ताजीराव उर्फ अण्णासाहेब तटकरे कांग्रेस पार्टी के नेता थे। ऐसे में कांग्रेस में प्रवेश करने के बाद उन्हें घर वापसी जैसा महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का नेतृत्व ही देश को आगे ले जा सकता है, इसी विश्वास के साथ उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया है। पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, उसे पूरी क्षमता और निष्ठा से निभाएंगे।

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सपकाल ने राज्य में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जहां भी अस्वच्छता और गंदगी है, उसे साफ किया जाना चाहिए। जिन होटल और कैंटीन में गंदगी पाई जा रही है, उनके लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। इसी तर्ज पर उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के कामकाज में भी गंदगी फैल रही है, इसलिए सरकार का ही 'लाइसेंस रद्द' किया जाना चाहिए।

जरांगे को दिए आश्वासन सार्वजनिक करने की मांग

मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे के अनशन पर बोलते हुए सपकाल ने आरोप लगाया कि भाजपा-महायुति सरकार ने मनोज जरांगे को दो बार आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने आंदोलन वापस लिया, लेकिन अब उन्हें दोबारा आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार ने जरांगे को पहले कौन-कौन से आश्वासन दिए थे, इसे सार्वजनिक किया जाए।

सपकाल ने आरोप लगाया कि आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा-महायुति सरकार जातियों के बीच विवाद पैदा करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में आरक्षण का मुद्दा सुलझाना चाहती है तो जातिवार जनगणना कराई जाए और कांग्रेस की इस मांग को स्वीकार किया जाए।

राज मेहरोल वाल्मीकि की महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अनुसूचित जाति विभाग के राज्य उपाध्यक्ष पद पर हुई नियुक्ति

मुंबई। महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने की दिशा में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के तहत राज मेहरोल वाल्मीकि को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अनुसूचित जाति विभाग के राज्य उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है।

उनकी नियुक्ति का राज्यभर के पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि यह नियुक्ति उनके संगठनात्मक कार्य और सामाजिक प्रतिबद्धता की उचित सराहना है।

राज मेहरोल वाल्मीकि ने अनुसूचित जाति विभाग के प्रशासन एवं मुख्यालयीन कार्यों की जिम्मेदारी लगातार चार वर्षों तक बेहद जिम्मेदारी के साथ संभाली है। इस दौरान उन्होंने संगठनात्मक समन्वय, प्रशासनिक

नियोजन, कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संपर्क तथा विभिन्न जनहित के मुद्दों पर प्रभावी ढंग से काम किया। सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति के सशक्तीकरण, युवाओं की भागीदारी और जमीनी स्तर पर जनता की समस्याओं को लेकर उन्होंने लगातार आवाज उठाते हुए पार्टी संगठन के लिए कार्य किया है।

नियुक्ति के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राज मेहरोल वाल्मीकि ने कहा, "मुझ पर जताए गए विश्वास को सार्थक करने के लिए मैं पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करूंगा। राज्य के प्रत्येक कार्यकर्ता में नई ऊर्जा का संचार कर पार्टी संगठन को और मजबूत बनाने तथा महाराष्ट्र की जनता के हित में लगातार प्रयासरत रहूंगा।"

उन्होंने पार्टी नेतृत्व, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, डॉ. सिद्धार्थ हत्तीअंबीरे तथा अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष अनिरुद्ध वनकर का हृदय से आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यभर के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के सहयोग से कांग्रेस पार्टी के जनाधार को और व्यापक बनाने के लिए वे पूरी ताकत से काम करेंगे।

'ई-20' के नाम पर मोदी-गडकरी-फडणवीस ने किया बड़ा घोटाला : हर्षवर्धन सपकाल

मुंबई। पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को लेकर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि एथेनॉल मिश्रण के जरिए सरकार में बैठे कुछ लाभार्थियों और उनके परिवारों को करोड़ों रुपये का फायदा पहुंचाया गया, जबकि इसका खामियाजा देश के लाखों वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। सपकाल ने इसे 'ई-20' घोटाला बताते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग की।

तिलक भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपकाल ने कहा कि ई-20 ईंधन से वाहनों में कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। उनके अनुसार, ई-20 से संबंधित निर्णय वर्ष 2030 में

लागू होना अपेक्षित था, लेकिन मोदी सरकार ने कुछ हितसंबंधित लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इसे जल्दबाजी में लागू किया। उन्होंने एथेनॉल की गुणवत्ता को लेकर सामने आ रही शिकायतों की जांच कराने की मांग भी की।

सपकाल ने दावा किया कि एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने में नितिन गडकरी की प्रमुख भूमिका रही है और उनके निर्णयों के कारण कई वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में बिचौलियों की भूमिका भी हो सकती है, जिसकी जांच कर सच्चाई सामने लाने की जरूरत है। सपकाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जनता से माफी मांगने की मांग की।

फडणवीस को दिल्ली भेजने की साजिश का आरोप

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर पूछे गए सवाल पर सपकाल ने आरोप लगाया कि उन्हें दिल्ली भेजने की राजनीतिक तैयारी चल रही है। उन्होंने दावा किया कि हिंदी थोपने का निर्णय भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है और महायुति सरकार में फडणवीस की राजनीतिक भूमिका सीमित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सपकाल ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में वास्तविक सत्ता केंद्रीय नेतृत्व के हाथों में है और देवेंद्र फडणवीस को भाजपा-आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति माना जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि फडणवीस को केंद्र में शिक्षा मंत्री बनाए जाने की तैयारी चल रही है। हालांकि, ये सभी आरोप हर्षवर्धन सपकाल द्वारा लगाए गए राजनीतिक दावे हैं।

एसआईआर कार्य में लापरवाही पड़ी भारी भिवंडी में बीएलओ शिक्षक पर मामला दर्ज

भिवंडी। राज्यभर में मतदाता सूचियों के गहन निरीक्षण अभियान एसआईआर (स्पेशल समरी रिवीजन) का काम जारी है। इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी प्रशासन की ओर से दी गई है। इसके बावजूद एसआईआर कार्य में लापरवाही बरतना भिवंडी के एक बीएलओ शिक्षक को भारी पड़ गया। काम में ढिलाई के आरोप में शिक्षक बीएलओ के खिलाफ रविवार को शांतिनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।

मामला दर्ज किए गए शिक्षक का नाम रवींद्र त्र्यंबक सदावर्ते है। सदावर्ते काल्हेर स्थित दिवंगत अनंत लक्ष्मण पाटिल कॉलेज में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें एसआईआर कार्य के लिए

बीएलओ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्हें मतदाता सूची से संबंधित फॉर्म वितरित करने तथा उनके डिजिटलाइजेशन का काम सौंपा गया था।

आरोप है कि सदावर्ते ने निर्धारित कार्य के तहत अब तक केवल 16 प्रतिशत फॉर्म का वितरण किया, जबकि फॉर्म के डिजिटलाइजेशन का काम महज 4 प्रतिशत ही पूरा किया। काम में कथित तौर पर टालमटोल और लापरवाही बरतने के चलते भिवंडी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के चुनाव कार्य नायब तहसीलदार मुबारक तड़वी ने रविवार को शांतिनगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

चुनावी ड्यूटी में तैनात शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की खबर से चुनावी कार्य में लगे अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों में भी हड़कंप मच गया है।

भिवंडी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, कई निचले इलाकों में भरा पानी

भिवंडी। शहर में रातभर हुई मूसलाधार बारिश के कारण सोमवार सुबह कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। भारी बारिश के चलते शहर से सटी कामवारी नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी, जिसके कारण नदी किनारे बसे कई इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ गई।

नदी नाका, ईदगाह रोड और म्हाडा कॉलोनी सहित कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया। ईदगाह क्षेत्र में कमर तक पानी भर जाने से स्थानीय निवासियों, विशेषकर महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों को घरों से बाहर निकलने और रोजमर्रा के कामकाज के लिए आवाजाही करने में भी परेशानी हुई।

वहीं, शहर की सब्जी मंडी और छत्रपति शिवाजी महाराज चौक

में भी बड़े पैमाने पर जलभराव देखने को मिला। पानी दुकानों में घुसने से व्यापारियों को नुकसान की चिंता सताने लगी, जबकि सब्जी विक्रेताओं और खरीदारी के लिए पहुंचे नागरिकों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। मूसलाधार बारिश और जलभराव के चलते शहर के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। स्थानीय नागरिकों ने जलनिकासी व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा जलभराव वाले क्षेत्रों में तत्काल राहत एवं निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है।

कामवारी नदी में बही मिनी बस, तेज बहाव में पुल के नीचे जाकर डूबी

भिवंडी। शहर में रातभर हुई मूसलाधार बारिश के कारण कामवारी नदी उफान पर आ गई। इसी दौरान तड़के नदी किनारे खड़ी एक मिनी बस तेज बहाव की चपेट में आकर नदी में बह गई और पुल के नीचे जाकर पानी में डूब गई।

कामवारी नदी क्षेत्र में महानगरपालिका की सीमा में लोकमान्य तिलक विसर्जन घाट स्थित है, जबकि इसके पास ही शेलार ग्राम पंचायत की सीमा में भी विसर्जन घाट बनाया गया है। इसी क्षेत्र में वाहनों की मरम्मत का

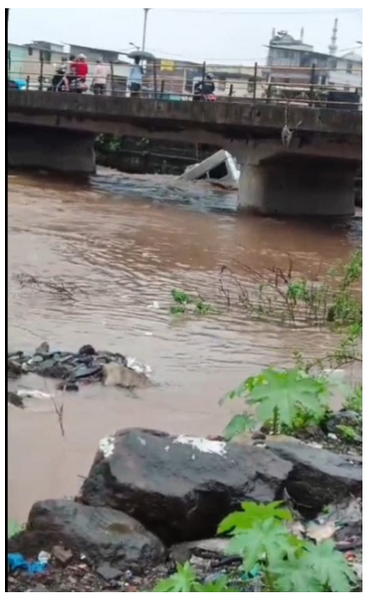

गैरेज संचालित होता है, जहां मरम्मत के लिए कई वाहन खड़े किए जाते हैं। बताया जा रहा है कि रातभर हुई मूसलाधार बारिश के चलते कामवारी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और पानी का बहाव बेहद तेज हो गया। इसी दौरान घाट परिसर में खड़ी मिनी बस बहकर नदी में चली गई और पुल के नीचे पानी में डूब गई।

कोहिनूर बिल्डिंग हादसा: मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 2 लाख मुआवजा देने की मांग

भिवंडी। भंडारी कंपाउंड स्थित गंगाराम वाडी में कोहिनूर नामक चार मंजिला इमारत गिरने की दर्दनाक घटना में 10 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद मुआवजे तथा प्रशासनिक लापरवाही को लेकर आवाज उठने लगी है। समाजवादी पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष मोहम्मद अनस अंसारी ने मनपा महापौर को पत्र देकर हादसे में मृतकों के परिवारों को महाराष्ट्र सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपये तथा घायलों को 2-2 लाख रुपये आर्थिक सहायता देने की मांग की है।

पत्र में मोहम्मद अनस अंसारी ने कहा कि कोहिनूर इमारत हादसा बेहद दुखद और हृदयविदारक

है। इस दुर्घटना में कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। ऐसे में पीड़ित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

सपा नेता ने भिवंडी शहर में घोषित की गई खतरनाक इमारतों को लेकर भी प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि महानगरपालिका द्वारा कई इमारतों को खतरनाक घोषित किए जाने के बावजूद वहां आज भी नल कनेक्शन और बिजली आपूर्ति जारी है, जिससे लोगों की जान खतरे में बनी हुई है। उन्होंने मांग की कि ऐसी सभी जर्जर और खतरनाक इमारतों को तत्काल खाली कराया जाए तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

मोहम्मद अनस अंसारी ने यह पत्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, भिवंडी मनपा आयुक्त, उपविभागीय अधिकारी और तहसीलदार को भी भेजा है। उन्होंने प्रशासन से शहर की सभी जर्जर एवं खतरनाक इमारतों का तत्काल सर्वे कराने तथा भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कार्रवाई करने की मांग की है।

टीईटी परीक्षा पेपर लीक मामले के सभी 15 आरोपियों को 17 अगस्त तक न्यायिक हिरासत

भिवंडी। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पेपर लीक मामले में भिवंडी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी 15 आरोपियों को सोमवार, 3 अगस्त को अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद भिवंडी अदालत ने सभी आरोपियों को 17 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

बताया जाता है कि 28 जून को महाराष्ट्र में होने वाली टीईटी परीक्षा का पेपर 26 जून को ही बेचने आए तीन लोगों को पकड़ने के बाद पेपर लीक मामले का खुलासा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए अब तक धीरज बलराज सिंह, राजीव शाव, आकाश कुमार

सरोज कुमार, सुमन कुमारी विजेंद्र गुप्ता, सोनू कुमार सिंह, मिथुन कुमार सिंह, कपिल कृष्णा दहिया, संजय कुमार सुरेशचंद्र शर्मा, बाबूलाल नारायण सिंह कुशवाहा, नरेश कुमार पुरनचंद माहौर उर्फ निक्की, पवन यादव, हरिओम सिंह पोनी, बिजेंद्र गुप्ता, इंद्रजीत सिंह उर्फ पीकू और सोनू कुमार दिवाकर सहित कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

इससे पहले भी अदालत ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा था। हालांकि, मामले के कथित मुख्य सूत्रधार बिजेंद्र गुप्ता, इंद्रजीत सिंह उर्फ पीकू और सोनू कुमार दिवाकर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन तीनों समेत अन्य 12 आरोपियों से आमने-सामने पूछताछ करने के लिए दोबारा पुलिस कस्टडी की मांग की थी।

पुलिस द्वारा सभी आरोपियों से एक साथ पूछताछ पूरी किए जाने के बाद सोमवार को उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया गया। आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता शैलेश गायकवाड़ ने बताया कि अदालत ने सभी 15 आरोपियों को 17 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।